<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

इरेडा के सीएमडी का आरबीआई नीतिगत संगोष्ठी में ग्रीन फाइनेंसिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विजन प्रस्तुत किया

नई दिल्ली, 13 मार्च 2025

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने आज जलवायु परिवर्तन जोखिम एवं वित्तपोषण के बारे में आरबीआई नीतिगत संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें जलवायु परिवर्तन जोखिमों के शमन और इसके वित्त पोषण के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख वित्तीय लीडरों को बुलाया गया था।

श्री दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के अक्षय ऊर्जा विस्तार के लिए वर्ष 2030 तक 40-46 लाख करोड़ रुपये (ई-मोबिलिटी और संबंधित बुनियादी ढांचे सहित) निवेश की आवश्यकता है, इसलिए वैश्विक फंडों को आकर्षित करने और घरेलू हरित वित्तपोषण बाजार को मजबूत करने के लिए नीतियां आवश्यक हैं। उन्होंने मूल्यांकन जोखिम के प्रबंधन में इरेडा जैसी विशेष हरित वित्तपोषण एजेंसी के महत्व को भी रेखांकित किया और बताया कि स्थापना के बाद से संचयी संवितरण के लिए 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बावजूद इरेडा के पास अब तक 200 करोड़ रुपये से कम की राशि है।

इरेडा के सीएमडी ने डेवलपर, ऋणदाता, विनियामक और नीति निर्माताओं के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु वित्तपोषण को और अधिक गति देने के लिए एक आदर्श पारिस्थितिकी प्रणाली को सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओंके क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के लिए उधार लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए एक एकीकृत, एकल-खिड़की प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक विजन के बारे में रेखांकित किया।

उन्होंने परियोजना के नकदी प्रवाह और व्यवहार्यता को जोखिम मुक्त करने के लिए बीमा समाधानों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार और अनुसंधान संस्थानों को जलवायु जोखिम की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी, एआई और वृहद डेटा का लाभ उठाना चाहिए, जिससे चरम मौसम की घटनाओं के विरुद्ध इस क्षेत्र की लचीलापन में वृद्धि हो । इसके अलावा, उन्होंने तापमान प्रतिरोधी सौर मॉड्यूल, प्रबलित पवन टरबाइन ब्लेड और उन्नत मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियों जैसे भारत-विशिष्ट समाधान विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया।

श्री दास ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवेश आकर्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर मानकीकृत हरित वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हुए सत्र का समापन किया। उन्होंने आगे बताया कि घरेलू पेंशन फंड, बीमा फंड और बैंकों के लिए निवेश अधिदेशों के लिए एयूएम दायित्वों को शुरू करके इस पहल को मजबूत किया जा सकता है। ये उपाय घरेलू हरित पूंजी बाजारों को सशक्त करेंगे और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के बारे में तेजी लाने के लिए मदद करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री जे.के. दाश द्वारा संचालित पैनल चर्चा में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें नाबार्ड के अध्यक्ष, श्री शाजी के.वी., केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ, श्री के. सत्यनारायण राजू, एनएबीएफआईडी के एमडी, श्री राजकिरण राय जी., बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ, श्री देबदत्त चंद, नीति आयोग, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम निदेशक, डॉ. आशु भारद्वाज और श्री प्रदीप कुमार दास शामिल थे। इससे पहले नीतिगत संगोष्ठी का उद्घाटन, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर द्वारा किया गया, तथा आरबीआई के गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा द्वारा मुख्य संदेश दिया गया ।